गरवी गुजरात

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD

वर्ष : 16
अंक : 058
दि. 27.06.2026,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

क्षेत्रीय आकांक्षाएँ,
वैश्विक महत्वाकांक्षाएँ

5 दिन बाकी

Vibrant GUJARAT REGIONAL CONFERENCES
Regional Aspirations, Global Ambitions
मध्य गुजरात
(वडोदरा)

गुजरात सरकार

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री भूपेन्द्रभाई पटेल
माननीय मुख्यमंत्री, गुजरात

29th | 30th JUNE 2026
वडोदरा

www.vibrantgujarat.com

नेता प्रतिपक्ष के दो वर्ष पूरे होने पर राहुल गांधी का संदेश; संविधान युवाओं और चुनावी पारदर्शिता के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखने का भरोसा

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) के रूप में दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने कार्यकाल को लोकतंत्र, संविधान और आम नागरिकों की आवाज को संसद तक पहुंचाने के लिए समर्पित बताते हुए कहा कि उनका राजनीतिक संघर्ष आगे भी पहले की तरह जारी रहेगा। सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी अपने संदेश में राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दो वर्षों का प्रत्येक दिन जनता के मुद्दों को सत्ता के केंद्र तक पहुंचाने और उन लोगों की आवाज बनने में बीता है, जिनकी समस्याएं अक्सर निर्णय लेने वाली संस्थाओं तक नहीं पहुंच पातीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि युवाओं, किसानों, छात्रों, श्रमिकों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर उनकी लड़ाई लगातार जारी रहेगी।

राहुल गांधी ने अपने संदेश में लिखा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में दो वर्ष पूरे होना उनके लिए केवल एक राजनीतिक पड़ाव नहीं, बल्कि जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को और अधिक मजबूती से निभाने का अवसर है। उन्होंने कहा कि इस अवधि में उनका एकमात्र उद्देश्य हर भारतीय की आवाज को संसद और सरकार तक पहुंचाना रहा है। उन्होंने लिखा कि वे पहले भी जनता के साथ खड़े थे, आज भी उनके साथ हैं और भविष्य में भी हर संघर्ष में आम लोगों के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक जनता का विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है और इसी भरोसे के साथ उनका सफर आगे बढ़ रहा है। अपने संदेश के अंत में उन्होंने लिखा, "सफर लंबा है, लेकिन मेरा संकल्प वही है। मैं आपके लिए हर लड़ाई लड़ता रहूंगा।" अपने कार्यकाल का उल्लेख करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पिछले दो वर्षों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों को लगातार उठाया। उन्होंने विशेष रूप से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) से जुड़े विवादों, छात्रों के भविष्य, रोजगार, किसानों की समस्याओं, सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता जैसे विषयों का उल्लेख किया। उनका कहना था कि संसद के भीतर और बाहर उन्होंने इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और सरकार से जवाबदेही सुनिश्चित करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने चुनावी धांधली के आरोपों और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता जैसे विषयों को भी अपने राजनीतिक अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। कांग्रेस के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने संसद में विपक्ष की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया। सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने, विभिन्न विधेयकों पर विस्तृत चर्चा की मांग करने तथा बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की आय, सामाजिक असमानता और आर्थिक नीतियों जैसे विषयों पर लगातार सरकार को घेरने की रणनीति अपनाई गई। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी ने विपक्ष की आवाज को संगठित करने के साथ-साथ विभिन्न दलों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राहुल गांधी का यह संदेश ऐसे समय आया है जब देश में कई राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बहस जारी है। कांग्रेस लगातार परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, युवाओं को रोजगार, किसानों की आय, जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय और संविधान की मूल भावना की रक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। पार्टी का कहना है कि आने वाले समय में भी इन विषयों को संसद और जनता के बीच प्रमुखता से रखा जाएगा।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी ने जून 2024 में संभाला था। इससे पहले लगातार लगभग दस वर्षों तक यह पद रिक्त रहा था। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में किसी भी विपक्षी दल के पास नेता प्रतिपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक संख्या नहीं थी। संसदीय परंपरा के अनुसार किसी दल के पास लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का कम से कम दस प्रतिशत यानी 55 सांसद होना आवश्यक माना जाता है। वर्ष 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटें जीतकर यह आंकड़ा पार किया, जिसके बाद राहुल गांधी को लोकसभा में आधिकारिक रूप से नेता प्रतिपक्ष का दायित्व सौंपा गया।

यह राहुल गांधी के सार्वजनिक जीवन का पहला औपचारिक संवैधानिक पद भी है। वर्ष 2004 में सक्रिय राजनीति में प्रवेश करने के बाद उन्होंने कांग्रेस संगठन और पार्टी के चुनावी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद पहली बार उन्हें मिला। इसके साथ ही गांधी परिवार में वे तीसरे ऐसे नेता बने जिन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस पद पर रह चुके हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी की भूमिका केवल संसदीय बहस तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को लेकर लगातार जनसंपर्क अभियान भी चलाए। दूसरी ओर, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं ने कई अवसरों पर राहुल गांधी के आरोपों और बयानों का विरोध करते हुए उन्हें तथ्यहीन बताया है। इस कारण संसद से लेकर चुनावी मंचों तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार तीखी राजनीतिक बहस देखने को मिली है। राहुल गांधी के दो वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर भी विभिन्न संदेश साझा किए। पार्टी नेताओं ने इसे विपक्ष की मजबूत आवाज और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण चरण बताया। वहीं राजनीतिक हलकों में राहुल गांधी के इस संदेश को आगामी संसदीय सत्र और भविष्य की राजनीतिक रणनीति के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। आने वाले समय में संसद के भीतर और बाहर सरकार तथा विपक्ष के बीच विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस और अधिक तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

गुजरात एटीएस की बड़ी कार्रवाई, 8.32 करोड़ रुपये की 2.08 लाख ट्रामाडोल गोलियां जब्त; राजस्थान से जुड़े ड्रग नेटवर्क का खुलासा

अहमदाबाद। गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) ने प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक दवाओं की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2.08 लाख ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट जब्त की हैं। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इनकी अनुमानित कीमत करीब 8.32 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस मामले में राजस्थान से जुड़े एक कथित ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि यह नेटवर्क लंबे समय से गुजरात और राजस्थान के बीच सक्रिय था तथा प्रतिबंधित दवाओं को वैध औषधियों की आड़ में विभिन्न राज्यों तक पहुंचाया जा रहा था। एटीएस अब इस पूरे सिंडिकेट के अन्य सदस्यों, सप्लाई चेन और वित्तीय लेन-देन की गहन जांच कर रही है। एटीएस अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई कई दिनों तक चली तकनीकी निगरानी, डिजिटल विश्लेषण और मानव स्रोतों से प्राप्त खुफिया सूचनाओं के आधार पर की गई। जांच एजेंसी को जानकारी मिली थी कि राजस्थान का मूल निवासी और वर्तमान में गुजरात के वलसाड जिले के पारडी क्षेत्र में रह रहा परेश पारसमल जैन बड़े पैमाने पर ट्रामाडोल की अवैध खरीद-बिक्री और तस्करी में शामिल है। सूचना की पुष्टि होने के बाद उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई और उसके संपर्कों की भी निगरानी की गई। जांच के दौरान पता चला कि 25 जून को आरोपी ने अंकलेश्वर से राजस्थान के पाली जिले के लिए प्रतिबंधित दवाओं की एक बड़ी खेप रवाना की थी। इस खेप को एमआर ट्रेवल्स की लग्जरी बस के माध्यम से भेजा गया था। पुलिस के अनुसार तस्करों ने प्रतिबंधित टैबलेटों को सामान्य दवाओं की खेप के रूप में दर्शाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि दवाओं को "न्यू महावीर मेडिकल" के नाम से जारी टैक्स इनवॉइस के साथ अन्य वैध औषधियों के बीच छिपाकर भेजा जा रहा था, ताकि जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके और किसी को संदेह न हो। एटीएस ने खुफिया सूचना के आधार पर पूरे परिवहन मार्ग की निगरानी की और संदिग्ध खेप को रोककर उसकी जांच की। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में 2 लाख 8 हजार ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट बरामद हुईं। अधिकारियों ने मौके पर ही पूरी खेप जब्त कर ली और आरोपी परेश पारसमल जैन को गिरफ्तार कर लिया। जब्त दवाओं को परीक्षण के लिए भेजा गया है तथा उनके स्रोत और निर्माण संबंधी जानकारी भी जुटाई जा रही है।

जांच एजेंसी का कहना है कि ट्रामाडोल एक शक्तिशाली दर्द निवारक दवा है, जिसका उपयोग चिकित्सकीय परामर्श के तहत गंभीर दर्द के इलाज में किया जाता है। हालांकि इसका दुरुपयोग नशे के रूप में भी किया जाता है। इसी कारण इसकी बिक्री, भंडारण और परिवहन पर कड़े कानूनी प्रावधान लागू हैं। बिना वैध अनुमति इतनी बड़ी मात्रा में इसका परिवहन मादक पदार्थ एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) तथा औषधि नियंत्रण संबंधी कानूनों के तहत गंभीर अपराध माना जाता है।

प्रारंभिक पूछताछ में जांच एजेंसियों को संदेह है कि आरोपी केवल एक कड़ी है और इसके पीछे एक संगठित नेटवर्क काम कर रहा है, जो प्रतिबंधित दवाओं को अलग-अलग राज्यों में सप्लाई करता है। एटीएस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप किस स्थान से प्राप्त की गई थी, इसे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था और इस पूरे नेटवर्क में कितने लोग शामिल हैं। इसके लिए आरोपी के मोबाइल फोन, बैंक खातों, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, डिजिटल उपकरणों और परिवहन दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या इस नेटवर्क का संबंध अन्य राज्यों में सक्रिय ड्रग सिंडिकेट से है। पुलिस उन मेडिकल प्रतिष्ठानों, थोक दवा विक्रेताओं और परिवहन एजेंसियों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिनके माध्यम से प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति की जा रही थी। यदि किसी संस्था या व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एटीएस अधिकारियों का कहना है कि हाल के वर्षों में मादक पदार्थों के साथ-साथ प्रतिबंधित साइकोट्रॉपिक दवाओं की अवैध तस्करी भी तेजी से बढ़ी है। अपराधी अब नशीली दवाओं को वैध दवाओं की खेप में छिपाकर या फर्जी बिल और टैक्स इनवॉइस तैयार कर विभिन्न राज्यों में भेजने जैसे नए तरीके अपना रहे हैं। इसी कारण जांच एजेंसियों ने दवा परिवहन, लॉजिस्टिक नेटवर्क और संदिग्ध मेडिकल सप्लाई चैनलों पर निगरानी और कड़ी कर दी है। गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम तथा अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एटीएस को उम्मीद है कि पूछताछ और डिजिटल साक्ष्यों के विश्लेषण से इस पूरे अंतरराज्यीय ड्रग नेटवर्क के अन्य सदस्यों तक पहुंच बनाई जा सकेगी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि गुजरात में प्रतिबंधित मादक पदार्थों और साइकोट्रॉपिक दवाओं की तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी इसी तरह सख्ती से जारी रहेगा।

राम मंदिर चढ़ावा मामले में बड़ा घटनाक्रम, चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा ने छोड़े पद; चंपत राय के पूर्व चालक समेत आठ आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की बरामदगी के बीच जांच तेज

अयोध्या। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित अनियमितताओं और चोरी के मामले ने शुक्रवार को नया मोड़ ले लिया। मामले में एफआईआर दर्ज होने और आठ आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय तथा ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा ने अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार दोनों ने जांच की निष्पक्षता बनाए रखने और किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, इस उद्देश्य से नैतिक आधार पर अपने पद छोड़े हैं। हालांकि इस बीच विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) की ओर से कहा गया कि उसे चंपत राय के इस्तीफे की आधिकारिक जानकारी नहीं है, जिससे इस घटनाक्रम को लेकर कुछ भ्रम भी बना हुआ है।

यह पूरा मामला राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित नकदी और अन्य चढ़ावे के कथित गबन से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की प्रारंभिक रिपोर्ट में चढ़ावे के प्रबंधन और निगरानी व्यवस्था में गंभीर अनियमितताओं की ओर संकेत किए जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद जांच एजेंसियों ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मामले में नामजद सभी आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रामाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जो चंपत राय के पूर्व चालक और मंदिर प्रबंधन से जुड़े रहे हैं, के अलावा लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र श्रीवास्तव और करुणेश पांडेय शामिल हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार इनमें से कुछ लोग मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे की गणना, संग्रहण और प्रबंधन से जुड़े कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से शामिल थे।

पुलिस ने सभी आरोपियों का चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया। अदालत ने सभी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और वित्तीय लेनदेन से जुड़े दस्तावेजों की भी गहन जांच की जा रही है।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 79.85 लाख रुपये नकद भी बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बरामद राशि और उपलब्ध दस्तावेजों का मिलान मंदिर के चढ़ावे के रिकॉर्ड से किया जा रहा है। एसआईटी की रिपोर्ट, बैंकिंग रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, लेखा अभिलेख और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की परत-दर-परत जांच जारी है।

मामले में चंपत राय और डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफों ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी व्यापक चर्चा छेड़ दी है। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने जांच प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के उद्देश्य से पद छोड़ने का निर्णय लिया। दूसरी ओर, वीएचपी के प्रवक्ता ने कहा है कि संगठन के पास चंपत राय के इस्तीफे की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है तथा उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चंपत राय का नाम पुलिस की एफआईआर में शामिल नहीं है और उन्होंने एसआईटी की जांच में पूरा सहयोग किया है।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी नहीं है और वे आधिकारिक सूचना मिलने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे।

उधर, विपक्षी दलों ने इस मामले को लेकर सरकार और ट्रस्ट दोनों पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का आरोप है कि एफआईआर में केवल निचले स्तर के कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम शामिल किए गए हैं, जबकि पूरे प्रकरण की जिम्मेदारी तय करने के लिए व्यापक जांच आवश्यक है। कुछ विपक्षी दलों ने मामले की उच्चस्तरीय या न्यायिक निगरानी में जांच कराने की मांग भी उठाई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी तरह साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ाई जा रही है और यदि जांच के दौरान किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद आवश्यकता पड़ने पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

देशभर के करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े इस मामले ने राम मंदिर में चढ़ावे की सुरक्षा, लेखा-जोखा और निगरानी व्यवस्था को लेकर भी कई प्रश्न खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें एसआईटी की विस्तृत जांच रिपोर्ट और पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं, जिससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कथित गबन का दायरा कितना बड़ा था और इसमें किन-किन लोगों की भूमिका रही।

संपादकीय

भरोसे के रिश्ते का कत्ल

आम भारतीय की स्मृति से एक साल पहले मेघालय में इंदौर की सोनम रघुवंशी द्वारा अपने हनीमून के दौरान पति राजा रघुवंशी की हत्या की घटना अभी मिटी नहीं है। सोनम ने पहाड़ी से अपने पति को धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया था। साजिश में उसका प्रेमी राज सिंह भी शामिल था। अब ऐसा ही मामला पुणे में सामने आया है जब सिया गोयल नामक युवती ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को लौहगढ़ स्थित ऊंची पहाड़ी से धक्का देकर मौत की नींद सुला दिया। दोनों धनाढ्य परिवारों से थे। इस साल की शुरुआत में सगाई हुई थी और इसी साल के अंत में उनकी शादी होने जा रही थी। हत्या की दोनों ही घटनाओं में प्रेम का दूसरा कोण मौजूद रहा। पहली घटना में खलनायक प्रेमी राज सिंह तो दूसरी घटना में चेतन चौधरी। दोनों ही घटनाओं में पति व मंगेतर को कांटा मानकर जीवन से हटाना और प्रेमी के दिखाए सब्जबाग संग जीने की उत्कट चाह थी। लेकिन ये कोई सामान्य दुर्घटनाएं नहीं हैं, एक सुनियोजित साजिश हैं,भरोसे के रिश्तों के कत्ल की। भारतीय समाज में ये घटनाएं अस्वाभाविक हैं और परिवार संस्था में भरोसा रखने वाले हर व्यक्ति को उद्वेलित करती हैं। यह समाज विज्ञानियों के लिये मंथन का विषय है कि कोई स्त्री कैसे अपने पति या होने वाली पति की हत्या करने की सोच बना लेती है? सोच बनाती ही नहीं है बल्कि उसे साजिश रचकर अंजाम भी देती है। यहां सवाल उठता है कि यदि सोनम व सिया परिवार द्वारा तय किए गए रिश्ते में नहीं बंधना चाहती तो ना कहने का साहस तो कर ही सकती थीं? निश्चय ही हत्या करने से ना कहना ज्यादा आसान है। धनाढ्य परिवार के केतन की तो अभी सगाई ही हुई थी, जिसे टाला भी जा सकता था। सिया के न चाहने पर परिवार के लोग केतन को खोने के बजाय रिश्ते को मन मारकर तोड़ देते।

निश्चय ही केतन व राजा रघुवंशी की सुनियोजित हत्याएं हमें परेशान करती हैं। भले ही ये घटनाएं इक्का-दुक्का हों, लेकिन समाज के विश्वास को गहरे तक खंडित करती हैं। कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी मधुर रिश्ते का ऐसा खौफनाक अंत हो सकता है। जिस सिया के साथ सुनहरे जीवन के सपने केतन ने देखे होंगे, उस पर तब क्या बीती होगी, जब उसने सिया को उसे पहाड़ी से धक्का देते हुए देखा होगा? उसके मां-बाप पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने उसकी शादी के लिये शाही तैयारियां शुरू कर दी थीं। हमारे समाज में वैवाहिक रिश्तों में पैदा होने वाली हिंसा, टकराव, अलगाव और कोर्ट-कचहरी का ट्रेंड गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। सवाल यह है कि नौ महीने कोख में रखने वाली मां और खून-पसीने से लालन-पालन करने वाले पिता के सोचे-विचारे फैसलों को नई पीढ़ी द्वारा क्यों खारिज किया जा रहा है? क्या समाज में दूषित खानपान, विषाक्त सोच का बाजार, रिश्तों में बढ़ता अविश्वास और एकाकी परिवारों का त्रास युवा पीढ़ी को आक्रामक बना रहा है? मोबाइल संस्कृति की घातकता व तेजी से फैलता नकारात्मक कंटेंट संबंधों में विकृतियां ला रहा है। मोबाइल फोन जो कभी रिश्तों को जोड़ता था, अपराध का साधन बन रहा है। सोनम व राज सिंह की साजिश हो या सिया व चेतन का षड्यंत्र, उसमें मोबाइल भी सहभागी बना है। पुलिस ने भी चेतन से हुई सिया की हजारों कॉलों का विवरण दिया है। आज साजिशें मोबाइल पर ही रची जाती हैं और मोबाइल से ही अंजाम दी जाती हैं। निश्चय ही सोनम व सिया की साजिशें वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने की सोच रहे युवाओं के मन में कई तरह के संशयों को जन्म देंगी। वजह साफ है कि इन हत्याओं से रिश्तों में विश्वास का खून हुआ है। नकारात्मक घटनाएं इक्का-दुक्का ही होती हैं लेकिन ये अप्रत्याशित व असमान्य घटनाएं आम आदमी की सोच को गहरे तक प्रभावित करती हैं। जो समाज में सहज-सरल रिश्तों के प्रति अविश्वास पैदा करती हैं। ऐसी सोच का नकारात्मक परिणाम भारतीय आदर्श स्त्री की प्रतिष्ठा पर भी आंच ला सकता है। यही वजह है कि आज नई पीढ़ी के कई युवा विवाह संस्था में प्रवेश से कतराने लगे हैं।

बड़ा मिशन लेकर सेशेल्स जा रहे हैं मोदी, हिंद महासागर में भारत का मास्टरस्ट्रोक देखेगी दुनिया

> हम आपको बता दें कि सेशेल्स 115 द्वीपों वाला छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मोजाम्बिक चैनल के निकट उन समुद्री मार्गों पर स्थित है, जहां से विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 27 से 29 जून तक होने वाली सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक सक्रियता और वैश्विक भूमिका को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस की स्वर्ण जयंती में मुख्य अतिथि के रूप में मोदी की भागीदारी यह संकेत देती है कि भारत अब हिंद महासागर में अपने मित्र देशों के साथ सुरक्षा, विकास और समुद्री सहयोग को और मजबूत करने की रणनीति पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।हम आपको बता दें कि सेशेल्स 115 द्वीपों वाला छोटा द्वीपीय राष्ट्र है, लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मोजाम्बिक चैनल के निकट उन समुद्री मार्गों पर स्थित है, जहां से विश्व व्यापार का बड़ा हिस्सा गुजरता है। इसी कारण अमेरिका, चीन और यूरोपीय शक्तियां भी इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं। ऐसे समय में भारत का सेशेल्स के साथ संबंध मजबूत करना हिंद महासागर में शक्ति संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इस यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण भारत द्वारा सेशेल्स तटरक्षक बल को एक तीव्र गश्ती पोत सौंपना है। इससे पहले भारत दो डोर्नियर विमान, कई गश्ती नौकाएं तथा तटीय निगरानी राडार प्रणाली भी सेशेल्स को प्रदान कर चुका है। भारतीय रक्षा कर्मियों की तैनाती और संयुक्त सैन्य अभ्यासों ने दोनों देशों के रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई दी है। समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय अपराधों से निपटने में सेशेल्स भारत पर भरोसा करता है। यही कारण है कि यह यात्रा हिंद महासागर में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक निर्णायक कदम मानी जा रही है।

हम आपको बता दें कि भारत की महासागर दृष्टि के अंतर्गत सेशेल्स को विशेष स्थान प्राप्त है। भारत अब केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में एक भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार की भूमिका निभा रहा है। सेशेल्स का कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में पूर्ण सदस्य बनने का संकेत भी इसी व्यापक रणनीति का हिस्सा है। इस समूह में भारत, मालदीव, मॉरीशस और श्रीलंका पहले से शामिल हैं। यदि सेशेल्स भी पूर्ण सदस्य बनता है, तो हिंद महासागर में भारत के नेतृत्व वाली क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और मजबूत होगी।

हम आपको बता दें कि मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमिनी के बीच होने वाली वार्ता में रक्षा सहयोग के साथ ऊर्जा, स्वास्थ्य, डिजिटल शासन, समुद्री निगरानी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। फरवरी 2026 में भारत ने सेशेल्स के लिए 175 मिलियन डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें ऋण सहायता और अनुदान दोनों शामिल हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सौर ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और आधारभूत ढांचे से जुड़ी अनेक परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। यह दर्शाता है कि भारत केवल सामरिक हितों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह विकास साझेदारी के माध्यम से भी अपने मित्र देशों के साथ दीर्घकालिक संबंध बना रहा है।

हम आपको बता दें कि भारत और सेशेल्स के संबंध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरे हैं। वर्ष 1770 में भारतीयों का पहला समूह वहां पहुंचा था। आज लगभग 15 हजार भारतीय मूल के लोग वहां रहते हैं, जो कुल जनसंख्या का बड़ा हिस्सा हैं। गुजराती और तमिल समुदाय व्यापार, निर्माण और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मोदी का भारतीय समुदाय से संवाद दोनों देशों के सामाजिक संबंधों को और मजबूत करेगा।

यह यात्रा वैश्विक राजनीति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रभाव का तेजी से विस्तार किया है। चीन की समुद्री परियोजनाएं, बंदरगाह निवेश और सामरिक उपस्थिति भारत के लिए चिंता का विषय रही हैं। ऐसे में सेशेल्स जैसे देशों के साथ भारत का गहरा सहयोग यह स्पष्ट संदेश देता है कि हिंद महासागर में भारत अपनी पारंपरिक भूमिका को और सशक्त बना रहा है। भारत की नीति अब केवल "पड़ोसी प्रथम" तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह "ग्लोबल साउथ" के नेतृत्वकर्ता के रूप में भी उभरना चाहता है। सेशेल्स यात्रा इसी व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है।

इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स की राष्ट्रीय सभा के विशेष अधिवेशन को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। यह दोनों देशों के राजनीतिक विश्वास और घनिष्ठता का प्रतीक माना जा रहा है। भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और रक्षा दल की भागीदारी भी यह दिखाती है कि दोनों देशों के संबंध केवल कूटनीतिक नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी में बदल चुके हैं।

बहरहाल, प्रधानमंत्री मोदी की सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर में भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति, समुद्री सुरक्षा नीति और वैश्विक प्रभाव का महत्वपूर्ण संकेत है। यह यात्रा भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना के केंद्र में स्थापित करने के साथ-साथ चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच संतुलन बनाने में भी सहायक होगी। विकास सहायता, रक्षा सहयोग, सांस्कृतिक संबंध और समुद्री साझेदारी के माध्यम से भारत यह संदेश दे रहा है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और साझा समृद्धि का सबसे भरोसेमंद साझेदार बनना चाहता है।

प्रेरणा

जीवन का सबसे बड़ा धर्म: माता-पिता के प्रति कर्तव्य

मानव जीवन में अनेक प्रकार के धर्म, कर्तव्य और उत्तरदायित्व बताए गए हैं, किंतु इन सभी में माता-पिता के प्रति सम्मान, सेवा और कृतज्ञता का स्थान सर्वोच्च माना गया है। जिस व्यक्ति ने हमें जन्म दिया, पालन-पोषण किया, कठिन परिस्थितियों में स्वयं कष्ट सहकर हमारे भविष्य को संवारने का प्रयास किया, उनके प्रति प्रेम और आदर प्रकट करना केवल सामाजिक दायित्व नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का सर्वोच्च स्वरूप है। इतिहास, धर्मग्रंथ और महान व्यक्तियों के जीवन प्रसंग बार-बार यही संदेश देते हैं कि जो संतान अपने माता-पिता का सम्मान करती है, उसका जीवन भी सम्मान और सुख से भर जाता है।

इतिहास में एक अत्यंत मार्मिक प्रसंग मुगल सम्राट शाहजहां और उनके पुत्र औरंगज़ेब से जुड़ा हुआ है। सत्ता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा में औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया। एक समय जिस सम्राट के आदेश पर विशाल साम्राज्य चलता था, वही अपने जीवन के अंतिम दिनों में एक कैदी का जीवन जीने के लिए विवश हो गया। कहा जाता है कि कैद के दौरान शाहजहां को प्रतिदिन एक टूटी हुई सुराही में पानी दिया जाता था। सुराही के टूटे होने के कारण पानी का अधिकांश भाग रास्ते में ही बह जाता और उनके पास बहुत कम पानी पहुंचता। वृद्धावस्था में प्यास की पीड़ा सहते हुए उन्होंने अधिक पानी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया, किंतु उनके पुत्र औरंगज़ेब ने उनकी इस प्रार्थना को भी स्वीकार नहीं किया। यह केवल एक पिता की प्यास नहीं थी, बल्कि उस संवेदना की परीक्षा थी जो किसी भी पुत्र के हृदय में अपने माता-पिता के प्रति स्वाभाविक रूप से होनी चाहिए।

इस घटना से अत्यंत व्यथित होकर शाहजहां ने फ़ारसी भाषा में एक मार्मिक संदेश लिखा। उन्होंने कहा कि, "हे पुत्र! तू बड़ा विचित्र मुसलमान है, जो अपने जीवित पिता को पानी के लिए तरसा रहा है। धन्य हैं वे हिंदू, जो अपने दिवंगत पूर्वजों को भी श्रद्धापूर्वक जल अर्पित करते हैं।" इस कथन में किसी धर्म की तुलना या आलोचना नहीं, बल्कि पुत्र धर्म की गहन व्याख्या छिपी हुई है। शाहजहां का आशय यह था कि यदि कोई समाज अपने दिवंगत पूर्वजों का भी स्मरण कर उन्हें श्रद्धा से जल अर्पित करता है, तो जीवित माता-पिता की सेवा और सम्मान का महत्व कितना अधिक होना चाहिए। यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।

यह प्रसंग हमें यह भी सिखाता है कि सत्ता, धन, वैभव और महत्वाकांक्षा यदि मनुष्य के भीतर से करुणा और संवेदनशीलता को समाप्त कर दें, तो वे किसी भी उपलब्धि को अर्थहीन बना देते हैं। औरंगज़ेब एक शक्तिशाली शासक अवश्य बना, लेकिन इतिहास में उसके व्यक्तित्व पर अपने पिता के प्रति कठोर व्यवहार का कलंक भी हमेशा जुड़ा रहा। दूसरी ओर शाहजहां की पीड़ा आज भी लोगों के हृदय को स्पर्श करती है और यह याद दिलाती है कि माता-पिता के प्रति कठोरता कभी भी महानता का प्रतीक नहीं हो सकती।

भारतीय संस्कृति में माता-पिता को देवताओं के समान सम्मान दिया गया है। वेदों और उपनिषदों में स्पष्ट रूप से कहा गया है—"मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।" अर्थात माता को देवता के समान मानो और पिता को भी देवता के समान सम्मान दो। हमारे यहां श्रवण कुमार की कथा हो या भगवान श्रीराम का अपने माता-पिता के प्रति समर्पण, हर उदाहरण यही बताता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा-पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि माता-पिता की सेवा में निहित है। यदि कोई व्यक्ति मंदिरों में जाकर पूजा करता है, दान-पुण्य करता है, किंतु अपने माता-पिता की उपेक्षा करता है, तो उसका धर्म अधूरा माना जाता है।

आज के आधुनिक युग में जीवन की भागदौड़, व्यस्तता और भौतिक उपलब्धियों की दौड़ ने पारिवारिक संबंधों को प्रभावित किया है। अनेक वृद्ध माता-पिता अपने ही बच्चों के रहते हुए अकेलेपन, उपेक्षा और मानसिक पीड़ा का सामना कर रहे हैं। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या इस बदलती सामाजिक सोच का संकेत है। यह स्थिति केवल सामाजिक समस्या नहीं, बल्कि नैतिक मूल्यों के क्षरण का भी प्रमाण है। जो माता-पिता अपने बच्चों के सुख के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, वही वृद्धावस्था में यदि सम्मान और अपनापन पाने के लिए तरसें, तो यह किसी भी सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है।

यह भी सत्य है कि माता-पिता केवल आर्थिक सहायता नहीं चाहते। उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता होती है अपने बच्चों के प्रेम, सम्मान, समय और आत्मीयता की। उनके साथ कुछ पल बैठकर बातचीत करना, उनकी भावनाओं को समझना, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना और उनके अनुभवों का सम्मान करना किसी भी महंगे उपहार से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। संतान का स्नेह उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होता है।

धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति चाहे कोई भी हो, संसार का प्रत्येक समाज माता-पिता के सम्मान को श्रेष्ठ मानता है। हर धर्म करुणा, सेवा और कृतज्ञता की शिक्षा देता है। इसलिए माता-पिता के प्रति प्रेम किसी विशेष परंपरा तक सीमित नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का साझा मूल्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत देने वाले माता-पिता का सम्मान नहीं कर सकता, उसके लिए समाज और मानवता के प्रति सच्ची संवेदना विकसित करना भी कठिन हो जाता है।

शाहजहां और औरंगज़ेब का यह प्रसंग केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गहरी सीख है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्ता, संपत्ति और सफलता क्षणिक हो सकती हैं, लेकिन माता-पिता के प्रति हमारा व्यवहार ही हमारे वास्तविक चरित्र का परिचय देता है। इतिहास उन लोगों को केवल उनकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उनके मानवीय आचरण से भी याद रखता है।

अंततः यही कहा जा सकता है कि संतान का सबसे बड़ा धर्म अपने माता-पिता के प्रति सम्मान, सेवा, प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करना है। उनके त्याग का ऋण कभी पूर्ण रूप से चुकाया नहीं जा सकता, किंतु अपने व्यवहार, संवेदनशीलता और समर्पण से उसे कुछ हद तक अवश्य कम किया जा सकता है। जो संतान अपने माता-पिता के आशीर्वाद को जीवन का सबसे बड़ा धन मानती है, उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता जाता है। यही सच्चा पुत्र धर्म है, यही मानवता का सर्वोच्च आदर्श है और यही वह मूल्य है जो किसी भी समाज को संस्कारित, संवेदनशील और महान बनाता है।

अशोक सिंघल से नजदीकी, इंदिरा ने भेजा जेल, रामलला के पटवारी की अनसुनी कहानी, जिसे देना पड़ा अपने पद से इस्तीफा

रामचरितमानस में कहा गया है कि होइ है सोई जो राम रचराखा। अयोध्या के जिस राम मंदिर को बनवाने के लिए 550 साल की लड़ाई राम भक्तों ने लड़ी जिसके लिए ना जाने कितने लोग जेल गए, कितनों ने प्राण दे दिए, कितनों की आंखें इंतजार में दुनिया छोड़कर चली गई। कितने मांओं ने अपने बच्चों को न्योछावर कर दिया। जब वो राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ तो लगा कि अब राजा राम की भक्ति में कोई कोर कसर नहीं रखी जाएगी। लेकिन क्या हमारे अपने राम भक्तों ने रामलला के मंदिर में लालच को नहीं छोड़ा, करप्शन कर दिया, पैसा लूट लिया भक्तों का। हां आरोप यही लग रहा है कि करोड़ों राम भक्त जो रामलला के दर्शन करने जाते हैं और अपनी औकात के हिसाब से 1, 100, सोना-चांदी, गहना मंदिर में चढ़ा कर आते हैं। यह आरोप लग रहा है कि उस पैसे में लूट घसोट हुई है। अयोध्या के राम मंदिर दान चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी और इसके बाद एक्शन का दौर भी शुरू हुआ। एफआईआर हुई, गिरफ्तारियां शुरू हुई और पूछताछ अभी भी जारी है। इस पूरे विवाद के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वह हैं चंपत राय। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के दो सदस्य चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में कठोर संस्तुति के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। आखिर कौन है चंपत राय? कैसे एक केमिस्ट्री प्रोफेसर राम मंदिर आंदोलन का सबसे प्रभावशाली चेहरा बन गया और अब जब चढ़ावे की कथित चोरी पर सवाल उठ रहे हैं तो उनके खिलाफ आवाजें क्यों तेज हो रही हैं? चंपत राय का जन्म 1946 में उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुआ था। कम उम्र में ही उनका जुड़ाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से हो गया। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने धामपुर के आश्रम डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर के रूप में नौकरी शुरू की। लेकिन उनकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला था। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया था। विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। जब देश में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही थी। तब चंपत राय बिजनौर के डिग्री कॉलेज में बच्चों को कैमेस्ट्री पढ़ा रहे थे। तभी अचानक कॉलेज के कॉरिडोर में शोर होने लगा। उन्होंने देखा तो गेट पर कुछ पुलिसकर्मी खड़े थे। फिर पुलिसवाले कॉलेज के प्रिंसिपल के पास चले गए। थोड़ी देर बाद कॉलेज का चपरासी चंपत राय की क्लास में आया और बोला कि आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। वो प्रिंसिपल के पास पहुंचे तब पुलिस वाले ने चंपत राय से कहा कि वो उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। तो चंपत राय ने कहा कि मैं अभी छात्रों को पढ़ा रहा हूं। आप अभी जाइए मैं अपनी क्लास खत्म करके खुद थाने आ जाऊंगा। चंपत राय सुनने के बाद पुलिसवाले वहां से चले गए। क्लास खत्म होने के बाद चंपत राय थाने पहुंचे जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वो 18 महीने जेल में रहे। चंपत राय की ये गिरफ्तारी इमरजेंसी के दौरान ही हुई थी। 1980 में जेल से रिहा होने के बाद चंपत राय ने नौकरी से इस्तीफा दिया। वो संघ के प्रचारक बन गए। संघ में उनके काम को देखते हुए तत्कालीन सरसंघचालक रज्जू भैय्या प्रभावित हो गए। उसके बाद उन्होंने राम मंदिर की लड़ाई लड़ने के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास में चंपत राय का नाम एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में दर्ज है, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर पूरी पटकथा लिखी। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बनने से पहले तक आम जनता में उनकी पहचान भले ही सीमित रही हो, लेकिन संघ और आंदोलन के भीतर उनका कद बेहद मजबूत था। चंपत राय की सबसे बड़ी खूबी उनका समावेशी दृष्टिकोण था। उन्होंने राम मंदिर आंदोलन को किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि सवर्ण समाज से आगे ले जाकर समाज के हर तबके तक इसकी पहुंच बनाई। देश भर में चले ऐतिहासिक 'शिला पूजन' और घर-घर से ईंटें जुटाने के अभियान के पीछे चंपत राय का ही दिमाग था। राम काज मिलने के बाद चंपत राय अवध के गांव गांव घूमे। अगर अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस का मुखर चेहरा थे, तो चंपत राय इसके मूक शिल्पकार थे, जो हमेशा लो-प्रोफाइल रहकर आंदोलन को धरातल पर आकार दे रहे थे। अशोक सिंघल के बेहद करीबी रहे एक प्रचारक के मुताबिक, चंपत राय को 1991 में अवध प्रांत के क्षेत्रीय मंत्री की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उस दौर में अयोध्या और आसपास के स्थानीय लोगों में मंदिर को लेकर चल रही लंबी कानूनी लड़ाई की वजह से एक तरह की निराशा घर कर गई थी। चंपत राय ने न सिर्फ इस निराशा को दूर किया, बल्कि स्थानीय समाज को सीधे आंदोलन से जोड़कर उनमें यह विश्वास जगाया कि कानूनी लड़ाई में हिंदू पक्ष की जीत निश्चित है।

राम जन्मभूमि से जुड़े तमाम कानूनी दस्तावेज, साक्ष्य और अदालती मुकदमों की बारीकियां चंपत राय की देखरेख में ही थीं। केस के हर पहलू पर उनकी सीधी पकड़ थी। अदालत की सुनवाई के दौरान वकीलों और आंदोलन से जुड़े लोगों के बीच समन्वय को जिम्मेदारी से संभाला। उनकी इसी मेहनत और समर्पण के कारण लोग उन्हें रामलला का पटवारी भी कहने लगे। जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ तब बने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चंपत राय को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई। यहीं से उनकी ताकत और प्रभाव दोनों बढ़े। मंदिर निर्माण, ट्रस्ट का प्रशासन, मीडिया से संवाद, व्यवस्थाएं, बड़े फैसलों पर चंपत राय सबसे प्रमुख चेहरे बनते गए।

अभियान

आत्मविजय का उत्सव: निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक, सामाजिक और मानवीय संदेश

भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहां प्रत्येक पर्व और व्रत केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारने, समाज को जोड़ने और प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व का बोध कराने का माध्यम भी बनता है। सनातन परंपरा में आने वाली प्रत्येक एकादशी का अपना अलग महत्व है, लेकिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी को विशेष रूप से अत्यंत पुण्यदायी और प्रभावशाली माना गया है। यह केवल एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि आत्मसंयम, ईश्वर के प्रति समर्पण, करुणा, दान, सेवा और अनुशासित जीवन का ऐसा संदेश देती है, जिसकी प्रासंगिकता आज के आधुनिक युग में और अधिक बढ़ गई है। जब मनुष्य सुविधाओं, उपभोग और भौतिक आकर्षणों के बीच अपने जीवन का संतुलन खोने लगता है, तब निर्जला एकादशी उसे यह याद दिलाती है कि वास्तविक शक्ति बाहर नहीं, बल्कि अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने में निहित है।

सनातन धर्म में भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनकर्ता और धर्म की रक्षा करने वाला देवता माना गया है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और संतुलन बिगड़ता है, तब भगवान विष्णु विभिन्न अवतारों के माध्यम से धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत भी उसी संरक्षण और संतुलन की भावना से जुड़ा हुआ है। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करते हैं, तुलसी को अर्पण करते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जप करके अपने मन को ईश्वर की भक्ति में स्थिर करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह दिन मनुष्य को अहंकार, लोभ, क्रोध और मोह जैसे आंतरिक विकारों से दूर होकर सात्विक जीवन अपनाने की प्रेरणा देता है।

निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। महाभारत की प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों में भीमसेन अपनी असाधारण भूख के कारण अन्य एकादशियों का व्रत नहीं रख पाते थे। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से इसका समाधान पूछा। तब महर्षि ने उन्हें वर्ष में केवल एक बार निर्जला एकादशी का कठोर व्रत रखने की सलाह दी और बताया कि इस व्रत का फल वर्षभर की समस्त एकादशियों के समान प्राप्त होगा। भीमसेन ने इस कठिन तपस्या को स्वीकार किया और उसी दिन से यह व्रत उनके नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। इस कथा का वास्तविक संदेश यह नहीं है कि केवल कठिन उपवास ही धर्म है, बल्कि यह है कि दृढ़ संकल्प, श्रद्धा और अनुशासन के साथ किया गया एक सार्थक प्रयास अनेक छोटे-छोटे प्रयासों के बराबर फलदायी हो सकता है।

निर्जला एकादशी का सबसे महत्वपूर्ण आधार आत्मसंयम है। मनुष्य का मन स्वभाव से चंचल होता है और इंद्रियां निरंतर विषयों की ओर आकर्षित होती रहती हैं। भोजन और जल जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। जब व्यक्ति स्वेच्छा से कुछ समय के लिए इन पर नियंत्रण रखता है, तब वह अपने भीतर छिपी मानसिक शक्ति का अनुभव करता है। यही कारण है कि भारतीय ऋषियों ने उपवास को शरीर को कष्ट देने का साधन नहीं, बल्कि मन को अनुशासित करने का विज्ञान माना। आत्मसंयम का यह अभ्यास व्यक्ति को धैर्यवान, संतुलित और आत्मविश्वासी बनाता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों में वही व्यक्ति सफल होता है जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लिया हो।

आज का युग उपभोगवाद का युग है। हर व्यक्ति अधिक से अधिक सुख-सुविधाएं प्राप्त करना चाहता है। नई-नई वस्तुएं, आधुनिक तकनीक, भौतिक संसाधन और विलासिता की जीवनशैली लोगों की प्राथमिकता बनती जा रही है। ऐसे समय में निर्जला एकादशी हमें यह सिखाती है कि वास्तविक समृद्धि इच्छाओं की पूर्ति में नहीं, बल्कि इच्छाओं पर नियंत्रण में है। जो व्यक्ति कम साधनों में भी संतुष्ट रहना सीख लेता है, वही जीवन की वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। संतोष और संयम ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को भीतर से समृद्ध बनाते हैं।

इस व्रत का सामाजिक पक्ष भी अत्यंत प्रेरणादायक है। भारतीय संस्कृति में पूजा और सेवा को एक-दूसरे का पूरक माना गया है। इसलिए निर्जला एकादशी के अवसर पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। भीषण गर्मी के मौसम में प्यासे को जल पिलाना, राहगीरों के लिए प्याऊ की व्यवस्था करना, गरीबों को घड़ा, छाता, वस्त्र, पंखा, फल, शर्बत तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं देना केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। दान का उद्देश्य केवल पुण्य अर्जित करना नहीं, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और सहयोग की भावना को बढ़ाना है। जब किसी जरूरतमंद के चेहरे पर सहायता मिलने से मुस्कान आती है, तभी दान का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण होता है।

निर्जला एकादशी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा हुआ है। यह व्रत वर्ष के उस समय आता है जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और जल का महत्व सबसे अधिक महसूस होता है। भारतीय संस्कृति में जल को केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार माना गया है। नदियों को माता कहा गया, वर्षा को वरदान माना गया और जल को पवित्रता का प्रतीक समझा गया। आज जब विश्व जल संकट, भूजल के लगातार घटते स्तर और नदियों के प्रदूषण जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, तब निर्जला एकादशी का संदेश और अधिक सार्थक हो जाता है। यह पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम जल की प्रत्येक बूंद का सम्मान करें, अनावश्यक जल व्यय रोकें, वर्षा जल संचयन को अपनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों का संरक्षण करें।

भारतीय परिवारों में यह व्रत केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं रहता। घरों में सामूहिक पूजा, कथा, भजन, आरती और धार्मिक चर्चा का आयोजन होता है। परिवार के बुजुर्ग बच्चों को इस व्रत का महत्व बताते हैं और इस प्रकार सांस्कृतिक परंपराएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं। आधुनिक जीवन की व्यस्तता में जहां परिवारों के पास एक-दूसरे के लिए समय कम होता जा रहा है, वहां ऐसे धार्मिक अवसर भावनात्मक निकटता बढ़ाने का कार्य करते हैं। सामूहिक पूजा परिवार के सदस्यों में विश्वास, सहयोग और अपनापन मजबूत करती है।

निर्जला एकादशी स्वास्थ्य के प्रति भी संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा देती है। शास्त्रों का उद्देश्य कभी भी शरीर को अनावश्यक कष्ट देना नहीं रहा। यदि कोई व्यक्ति आयु, बीमारी, गर्भावस्था या अन्य स्वास्थ्य कारणों से निर्जल व्रत रखने में सक्षम नहीं है, तो वह अपनी क्षमता के अनुसार फलाहार या जल ग्रहण करके भी श्रद्धापूर्वक भगवान का स्मरण कर सकता है। धर्म का मूल आधार भावना है, प्रदर्शन नहीं। भगवान श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, केवल बाहरी कठोरता को नहीं। इसलिए विवेक और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए व्रत करना ही उचित माना गया है।

यह व्रत हमें समय के महत्व का भी बोध कराता है। व्रत से एक दिन पूर्व सात्विक भोजन करना, प्रातःकाल जल्दी उठना, स्नान करना, पूजा की तैयारी करना, दिनभर संयम रखना और अगले दिन विधिपूर्वक पारण करना—यह पूरी प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर अनुशासन विकसित करती है। नियमित और व्यवस्थित जीवन ही सफलता की आधारशिला है। जो व्यक्ति छोटी-छोटी बातों में अनुशासन का पालन करता है, वही बड़े लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकता है।

निर्जला एकादशी का आध्यात्मिक पक्ष आत्मशुद्धि से जुड़ा हुआ है। उपवास के दौरान मनुष्य केवल भोजन का त्याग नहीं करता, बल्कि उसे अपने भीतर के नकारात्मक विचारों का भी त्याग करना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कटु वचन, अहंकार और लालच जैसे दोषों से मुक्त होकर यदि मनुष्य प्रेम, करुणा, सत्य, क्षमा और विनम्रता को अपनाता है, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। केवल भूखे रहने से धर्म की सिद्धि नहीं होती, बल्कि मन की पवित्रता और आचरण की श्रेष्ठता ही वास्तविक साधना है।

आज की पीढ़ी के लिए निर्जला एकादशी का संदेश अत्यंत उपयोगी है। प्रतिस्पर्धा, तनाव, मानसिक दबाव और अनिश्चितताओं से भरे इस दौर में आत्मसंयम और मानसिक संतुलन सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुके हैं। यह व्रत सिखाता है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं का दास नहीं, बल्कि उनका स्वामी बन सकता है।

PRGI NO. GUJHIN/2011/39228 Printed, Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HARDIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmdabad-380 002 and Published from TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005. Editor : MANOJKUMAR CHAMPAKLAL SHAH
Rage.Office: TF-01, Nanakram Super Market, Ramnagar, Sabarmati, Ahmedabad - 380 005 Gujarat,India. Phone : (O) 9016333307(M)9328333307,9825333307
Email : garvigujarat2007@gmail.com*garvigujarat2007@yahoo.com*Website : www.garvigujarat.co.in

देशभर में साइबर ठगी फैलाने वाले एपीके रैकेट का पर्दाफाश, गुजरात पुलिस ने झारखंड से तीन मास्टरमाइंड दबोचे, हर महीने 50 लाख तक की कमाई

अहमदाबाद। गुजरात पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने देशभर में हजारों लोगों को निशाना बनाने वाले एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए झारखंड के गिरिडीह-जामताड़ा क्षेत्र से संचालित गिरोह के तीन प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी ऐसे खतरनाक एंड्रॉयड एप्लिकेशन पैकेज (एपीके) तैयार करते थे, जिन्हें बैंक, गैस कंपनी, बिजली विभाग, सरकारी योजनाओं और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के नाम पर लोगों के मोबाइल फोन में इंस्टॉल कराया जाता था। एक बार एप डाउनलोड होते ही मोबाइल पूरी तरह साइबर अपराधियों के नियंत्रण में चला जाता था और बैंक खातों से लाखों रुपये निकाल लिए जाते थे। पुलिस का दावा है कि यह गिरोह देशभर में सक्रिय साइबर अपराधियों को एपीके फाइलें उपलब्ध कराकर हर महीने 40 से 50 लाख रुपये तक की कमाई कर रहा था।

साइबर क्राइम ब्रांच की संयुक्त पुलिस आयुक्त डॉ. लवीना सिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया कि मामले की जांच अहमदाबाद के हंसोल निवासी नरेश सबनानी की शिकायत के बाद शुरू की गई। शिकायतकर्ता को व्हाट्सऐप पर एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें स्वयं को साबरमती गैस लिमिटेड का प्रतिनिधि बताते हुए गैस कनेक्शन बंद किए जाने की चेतावनी दी गई थी। संदेश में एक मोबाइल नंबर पर संपर्क करने और "साबरमती गैस बिल अपडेट.एपीके" नामक एप डाउनलोड करने के लिए कहा गया। शिकायतकर्ता ने जैसे ही एप इंस्टॉल किया, उसका मोबाइल हैक हो गया और कुछ ही समय में उसके एचडीएफसी बैंक खाते से 6.68 लाख रुपये निकाल लिए गए। पीड़ित ने तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई।

तकनीकी विश्लेषण, डिजिटल ट्रैकिंग और खुफिया सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने इस साइबर नेटवर्क तक पहुंच बनाई। जांच में सामने आया कि गिरोह का सरगना 28 वर्षीय पूर्णानंद उर्फ मुकेश तिवारी है, जो झारखंड के गिरिडीह जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसे रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की सहायता से किशनगंज के पास एक चलती ट्रेन से गिरफ्तार किया। उसके साथ 33 वर्षीय विकास दास और 26 वर्षीय सीताराम नकुल मंडल को भी गिरफ्तार किया गया।

जांच में खुलासा हुआ कि मुकेश तिवारी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर दुर्भावनापूर्ण एपीके फाइलें तैयार करता था। इसके बाद वह एक विशेष टेलीग्राम बॉट के माध्यम से इन्हें देशभर में सक्रिय साइबर अपराधियों को बेचता था। पुलिस के अनुसार इस बॉट में विभिन्न बैंकों, सरकारी सेवाओं और सार्वजनिक संस्थानों के नाम पर तैयार कई प्रकार के फर्जी एप उपलब्ध थे। साइबर अपराधी इन एप्स को खरीदकर आम लोगों को व्हाट्सऐप, टेलीग्राम, एसएमएस और अन्य डिजिटल माध्यमों से भेजते थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी अब तक कम से कम 18 प्रमुख बैंकों के नाम पर फर्जी एपीके फाइलें तैयार कर चुका था। इनमें एसबीआई केवाईसी, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा,

एक्सिस बैंक, यस बैंक, यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक सहित कई वित्तीय संस्थानों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आरटीओ ई-चालान, बिजली बिल, गैस बिल, ग्राहक सेवा, सरकारी योजनाओं और अन्य सेवाओं के नाम पर भी नकली एप बनाए गए थे। इन फर्जी एप्स की मासिक सदस्यता लगभग 12 हजार रुपये में बेची जाती थी। पुलिस का कहना है कि गिरोह के पास हर महीने 300 से 400 ग्राहक होते थे, जिससे उसे लगभग 40 से 50 लाख रुपये की आय होती थी।

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी विकास दास इस पूरे नेटवर्क में भुगतान और वितरण का काम संभालता था। वह एपीके फाइलें खरीदने वाले साइबर अपराधियों से राशि प्राप्त करता और एसबीआई की योनो कैश सुविधा के माध्यम से बिना डेबिट कार्ड एटीएम से नकदी निकलवाने की व्यवस्था करता था। अपना कमीशन काटने के बाद शेष रकम वह मुख्य आरोपी मुकेश तिवारी तक पहुंचाता था।

तीसरे आरोपी सीताराम नकुल मंडल की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार वह अन्य साइबर अपराधियों को एपीके फाइलें उपलब्ध कराने के अलावा डेबिट और क्रेडिट कार्ड से संबंधित गोपनीय जानकारियां जुटाने का काम करता था। जांच में यह भी सामने आया कि वह पहले ओटीपी हासिल कर बैंक खातों से रकम उड़ाने वाली साइबर ठगी में भी शामिल रह चुका है।

साइबर क्राइम ब्रांच के अनुसार गिरोह बेहद सुनियोजित तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाता था। फर्जी एप कभी गैस बिल अपडेट के नाम पर भेजे जाते थे तो कभी बैंक केवाईसी, बिजली बिल, ग्राहक सेवा, सरकारी सब्सिडी, ई-चालान या यहां तक कि शादी के निमंत्रण पत्र के रूप में भी लोगों तक पहुंचाए जाते थे। जैसे ही कोई व्यक्ति एप डाउनलोड करता, वह उसके मोबाइल में मौजूद एसएमएस, संपर्क सूची, कॉल लॉग, बैंकिंग एप, नोटिफिकेशन और अन्य संवेदनशील जानकारियों तक पहुंच हासिल कर लेता था। इसके बाद साइबर अपराधी ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड और अन्य जानकारी हासिल कर खाते से रकम निकाल लेते थे।

डॉ. लवीना सिन्हा ने बताया कि इन एपीके फाइलों की सबसे खतरनाक विशेषता यह थी कि संक्रमित मोबाइल से वे स्वतः ही व्हाट्सऐप और टेलीग्राम समूहों में अन्य लोगों को भी भेजी जाती थीं। इस वजह से एक ही फर्जी एप कुछ ही घंटों में हजारों मोबाइल फोन तक पहुंच जाता था और साइबर ठगी का दायरा लगातार बढ़ता जाता था।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों और संस्थानों के नाम पर तैयार की गई अनेक एपीके फाइलें, सर्वर, डोमेन, ईमेल अकाउंट, डिजिटल उपकरण और अन्य तकनीकी साक्ष्य बरामद किए हैं। इनकी फॉरेंसिक जांच की जा रही है ताकि गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

प्रारंभिक जांच में इस गिरोह को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज कम से कम 12 शिकायतों तथा अहमदाबाद में दर्ज पांच अलग-अलग एफआईआर से जोड़ा गया है। इन मामलों में अब तक लगभग 70 लाख रुपये की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। हालांकि पुलिस का मानना है कि गिरोह की गतिविधियां कई राज्यों तक फैली हुई थीं और वास्तविक ठगी की राशि इससे कहीं अधिक हो सकती है। विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पूरे नेटवर्क की जांच आगे बढ़ाई जा रही है।

पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान लिंक या व्हाट्सऐप संदेश के माध्यम से प्राप्त एपीके फाइल को कभी डाउनलोड न करें। केवल आधिकारिक गूगल प्ले स्टोर या अधिकृत ऐप स्टोर से ही एप इंस्टॉल करें। किसी भी व्यक्ति के साथ ओटीपी, बैंकिंग पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी साझा न करें। यदि गलती से कोई संदिग्ध एप डाउनलोड हो जाए या साइबर ठगी का संदेह हो तो तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें अथवा निकटतम साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस का कहना है कि डिजिटल सतर्कता ही इस प्रकार की संगठित साइबर ठगी से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है।

साबरमती-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन अब 'अमृत भारत' रैक से होगी संचालित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं मांग को ध्यान में रखते हुए साबरमती–हरिद्वार साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरों का विस्तार करने के साथ-साथ इसे अत्याधुनिक अमृत भारत रैक से संचालित करने का निर्णय लिया गया है। विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 09425 साबरमती-हरिद्वार स्पेशल जिसे 29 जून 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 27 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन 6 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक अमृत भारत रैक से संचालित होगी।

ट्रेन संख्या 09426 हरिद्वार-साबरमती स्पेशल जिसे 30 जून 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 28 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है। यह ट्रेन 7 जुलाई से 28 जुलाई 2026 तक अमृत भारत रैक से संचालित होगी।

इस ट्रेन में स्लीपर एवं सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09425 के विस्तारित फेरों की बुकिंग 28 जून 2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू होगी।

ट्रेनों के परिचालन समय, ठहराव और संरचना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भावनगर–सुरेन्द्रनगर गेट सेक्शन का किया विंडो ट्रेलिंग एवं संरक्षा निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने शुक्रवार, 26 जून, 2026 को भावनगर परा से सुरेन्द्रनगर गेट स्टेशन तक विस्तृत विंडो ट्रेलिंग एवं संरक्षा निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खोडीयार मंदिर, सोनगढ़, बजूद, सणोसरा, धोला, बोटाद, लींबडी तथा सुरेन्द्रनगर गेट स्टेशनों का संरक्षा, परिचालन, अधोसंरचना एवं यात्री सुविधाओं के दृष्टिकोण से गहन अवलोकन किया।

भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने उक्त रेलखंड में प्रगति पर चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का विशेष रूप से जायजा लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, निर्धारित संरक्षा मानकों के अनुपालन तथा कार्यों की

प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान श्री वर्मा ने रेल पथ, सिग्नल एवं दूरसंचार प्रणाली सहित विभिन्न रेल अधोसंरचना संबंधी व्यवस्थाओं का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया। उन्होंने रेल परिसंपत्तियों के समुचित रखरखाव तथा संरक्षा मानकों के शत-प्रतिशत अनुपालन पर विशेष बल दिया।

बोटाद स्टेशन पर उन्होंने रेलवे कॉलोनी का निरीक्षण किया तथा वहां निवासरत रेलवे कर्मचारियों के परिजनों से संवाद कर उनकी आवश्यकताओं एवं सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की।

मंडल रेल प्रबंधक ने स्टेशन परिसरों की स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था, प्रतीक्षालय, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए श्री वर्मा ने कहा कि रेल संचालन में संरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा संरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन प्रत्येक रेलकर्मी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से उच्च स्तर की सतर्कता, बेहतर समन्वय एवं कार्यकुशलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया।

इस अवसर पर भावनगर मंडल के विभिन्न विभागों के शाखा अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी उपस्थित रहे।

'बिजली की बचत ही बिजली उत्पादन' के मंत्र के साथ सरकारी कार्यालयों में बिजली बचत अभियान का शुभारंभ

▸▸ सूर्यप्रकाश से सोलर तक; गुजरात सरकार का ग्रीन एनर्जी रोडमैप : सरकारी कार्यालयों में ऊर्जा बचत संबंधी दिशानिर्देश जारी

▸▸ बिजली बचत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालय को सम्मानित किया जाएगा

▸▸ सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखना होगा

▸▸ कार्यालयों के कॉरिडोर, मीटिंग रूम, पार्किंग तथा शौचालयों में स्वतः संचालित होने वाले ऑक्यूपेंसी सेंसर तथा टाइमर आधारित ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे

गांधीनगर : ग्लोबल वार्मिंग तथा दिन-प्रतिदिन बढ़ते तापमान के कारण बिजली की मांग में लगातार वृद्धि हो रही है। इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य के सभी सरकारी-अर्ध सरकारी कार्यालयों, बोर्ड-निगमों तथा सार्वजनिक भवनों में ऊर्जा दक्षता एवं ऊर्जा बचत के लिए एक व्यापक अभियान प्रारंभ किया गया है।

गुजरात सरकार के ऊर्जा बचाओ अभियान अंतर्गत ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल तथा सड़क एवं भवन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यक्षमता को प्रभावित किए बिना अनावश्यक बिजली की खपत कम करके वित्तीय अनुशासन तथा पर्यावरणीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन तथा ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के सभी विभागों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा उत्पादन, टिकाऊ विकास तथा लागत-प्रभावशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के सरकारी कार्यालय तथा प्रशासनिक भवन संस्थागत बिजली खपत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जहां कार्यक्षमता को प्रभावित किए बिना बड़े पैमाने पर ऊर्जा की बचत की जा सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली बचत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कार्यालयों को राज्य सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जिम्मेदारीपूर्ण ऊर्जा उपयोग की व्यवस्था लागू की गई है। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद, सप्ताहांत अथवा सार्वजनिक अवकाश के दिनों में सभी लाइटें, पंखे, एयर कंडीशनर तथा कंप्यूटर सिस्टम अनिवार्य रूप से बंद रखने होंगे। जो अधिकारी अवकाश पर अथवा फील्ड ड्यूटी पर हों, उनकी खाली केबिनों में भी सभी विद्युत उपकरण बंद रखने के लिए कार्यालय प्रमुखों को प्रतिदिन निगरानी रखनी होगी। साथ ही प्रत्येक बड़े विभाग में एक 'नोडल अधिकारी' की नियुक्ति की जाएगी।

बीईई की अधिसूचना के अनुसार सभी सरकारी कार्यालयों में एयर कंडीशनर का डिफॉल्ट तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त, मैन्युअल त्रुटियों के कारण होने वाली बिजली की बर्बादी रोकने के लिए कार्यालयों के कॉरिडोर, मीटिंग रूम, पार्किंग क्षेत्र तथा शौचालयों में स्वतः संचालित ऑक्यूपेंसी सेंसर एवं टाइमर आधारित ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम स्थापित किए जाएंगे। कार्यालय समय समाप्त होने के बाद अर्थात शाम 6 बजे से वॉटर कूलर बंद रखने तथा प्रातः 9 बजे के बाद ही चालू करने की सख्त व्यवस्था की जाएगी।

ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सुधार के अंतर्गत सभी सरकारी भवनों में पुरानी पारंपरिक लाइटों के स्थान पर बिजली बचाने वाली आधुनिक एलईडी लाइटें लगाई जाएंगी तथा भविष्य में होने वाली खरीद में केवल 5-स्टार रेटिंग वाले उपकरणों को प्राथमिकता दी जाएगी। महानगर पालिकाओं एवं नगर पालिकाओं में सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम (सीसीएम) के माध्यम से स्ट्रीट लाइटों के चालू एवं बंद होने का समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के खगोलीय समय से केंद्रीय रूप से जोड़ा जाएगा, जिससे प्रतिदिन लगभग 60 मिनट की प्रत्यक्ष बिजली बचत होगी। इसके अतिरिक्त; रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक कम यातायात वाले समय में प्रायोगिक आधार पर एकांतर पोलों की स्ट्रीट लाइटें बंद रखने की भी योजना बनाई गई है।

इसके अलावा; बहुमंजिला भवनों में लिफ्ट के उपयोग को कम कर सीढ़ियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता संबंधी पोस्टर लगाए जाएंगे। दिन के समय पर्याप्त सूर्यप्रकाश उपलब्ध होने पर न्यूनतम प्रकाश व्यवस्था का उपयोग सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। जिन सरकारी कार्यालयों में पर्याप्त खुली जगह उपलब्ध होगी, वहां सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करने की आवश्यक योजना बनाई जाएगी। जीईडीए द्वारा जिन सरकारी भवनों में बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, उनकी जांच की जाएगी तथा यदि वे कार्यरत नहीं हैं तो उन्हें पुनः चालू कर उनकी निर्धारित क्षमता के अनुरूप बिजली उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल तथा सड़क एवं भवन विभाग द्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्ति में जानकारी दी है कि राज्य सरकार के इन आदेशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र तैयार किया गया है। सभी विभागों को आगामी 45 दिनों के भीतर अपना 'ऑफिस एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान' तैयार कर गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईएडी) को सबमिट करना होगा। इसके अतिरिक्त; ऊर्जा उपयोग संबंधी त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी तथा प्रत्येक वर्ष थर्ड-पार्टी एनर्जी ऑडिटरों द्वारा अनिवार्य ऊर्जा ऑडिट कराया जाएगा। जो कार्यालय इस अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे; उन्हें प्रोत्साहित करते हुए सम्मानित भी किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे द्वारा अहमदाबाद–पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से अहमदाबाद–पटना साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के फेरे विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है :

ट्रेन संख्या 09447 अहमदाबाद-पटना साप्ताहिक स्पेशल जिसे 24 जून, 2026 तक अधिसूचित किया गया था उसे अब बढ़ाकर 01 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09448 पटना-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल जिसे 26 जून 2026 तक अधिसूचित किया गया था, उसे अब बढ़ाकर 03 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09447 के विस्तारित फेरों की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू है। ट्रेनों के ठहराव, संरचना एवं समय के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

लखनऊ स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित

उत्तर रेलवे के लखनऊ स्टेशन पर इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य के अंतर्गत ओएचई (OHE) संशोधन कार्य हेतु ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनों का मार्ग अस्थायी रूप से परिवर्तित रहेगा। साथ ही कुछ ट्रेनों को वैकल्पिक स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव भी प्रदान किया जाएगा।

इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 15667 गांधीधाम–कामाख्या साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 27 जून से 12 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल–लखनऊ–बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल–ऐशबाग–मल्हौर–बाराबंकी के रास्ते चलेगी।

ट्रेन संख्या 15668 कामाख्या–गांधीधाम साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 01 जुलाई से 9 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी–लखनऊ–कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी–मल्हौर–ऐशबाग–कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेगी।

ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम–भागलपुर स्पेशल दिनांक 26 जून से 10 जुलाई, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग मानकनगर-लखनऊ–मल्हौर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानक नगर–ऐशबाग–मल्हौर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर–गांधीधाम स्पेशल दिनांक 29 जून और 6 जुलाई, 2026 को निर्धारित मार्ग मल्हौर–लखनऊ–मानक नगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मल्हौर–ऐशबाग–मानक नगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 19409 साबरमती–गोरखपुर द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 11 जुलाई से 12 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग मानक नगर-लखनऊ-मल्हौर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मानक नगर–ऐशबाग–मल्हौर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 19410 गोरखपुर–साबरमती द्वि साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 11 जुलाई से 12 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी–लखनऊ–मानक नगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी–मल्हौर–ऐशबाग–मानक नगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान बादशाहनगर एवं ऐशबाग स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 15270 साबरमती–मुजफ्फरपुर जनसाधारण एक्सप्रेस दिनांक 11 जुलाई से 12 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल–लखनऊ–बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल–ऐशबाग–मल्हौर–बाराबंकी के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 15635 ओखा–गुवाहाटी साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 26 जून से 11 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग कानपुर सेंट्रल–लखनऊ–बाराबंकी के स्थान पर परिवर्तित मार्ग कानपुर सेंट्रल–ऐशबाग–मल्हौर–बाराबंकी के रास्ते चलेगी।

ट्रेन संख्या 15636 गुवाहाटी–ओखा साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 29 जून से 7 सितंबर, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग बाराबंकी–लखनऊ–कानपुर सेंट्रल के स्थान पर परिवर्तित मार्ग बाराबंकी–मल्हौर–ऐशबाग–कानपुर सेंट्रल के रास्ते चलेगी।

ट्रेन संख्या 19168 वाराणसी सिटी–अहमदाबाद (साबरमती) एक्सप्रेस दिनांक 26 जून से 10 जुलाई, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग मल्हौर–लखनऊ–मानक नगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मल्हौर–ऐशबाग–मानक नगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 19166 दरभंगा–अहमदाबाद (साबरमती) एक्सप्रेस दिनांक 27 जून से 11 जुलाई, 2026 तक अपने निर्धारित मार्ग मल्हौर–लखनऊ–मानक नगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग मल्हौर–ऐशबाग–मानक नगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान ऐशबाग एवं बादशाहनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 20940 सुल्तानपुर–साबरमती साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 1 एवं 8 जुलाई, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग उतरेटिया–लखनऊ–आलमनगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग उतरेटिया–ट्रांसपोर्ट नगर–आलमनगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान उतरेटिया एवं आलमनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

ट्रेन संख्या 20964 वाराणसी–साबरमती साप्ताहिक एक्सप्रेस दिनांक 27 जून तथा 4, 11 जुलाई, 2026 को अपने निर्धारित मार्ग उतरेटिया–लखनऊ–आलमनगर के स्थान पर परिवर्तित मार्ग उतरेटिया–ट्रांसपोर्ट नगर–आलमनगर के रास्ते चलेगी। इस दौरान उतरेटिया एवं आलमनगर स्टेशनों पर अतिरिक्त ठहराव प्रदान किया जाएगा।

यात्रियों से अनुरोध है कि उपर्युक्त बदलाव को ध्यान में रखकर अपनी यात्रा प्रारम्भ करें। ट्रेनों के ठहराव, समय और संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पिथोरा चित्रकला: दीवारों से कैनवास तक का सफर

मानव और ईश्वर के बीच सामंजस्य की एक प्राचीन प्रार्थना ने कैसे पारंपरिक सीमाओं को पार कर अभूतपूर्व आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया

गांधीनगर : आगामी वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन (VGRC) के अंतर्गत मध्य गुजरात क्षेत्र का सम्मेलन 29 और 30 जून 2026 को वडोदरा स्थित GSFC यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह सम्मेलन हस्तशिल्प क्षेत्र को भी विशेष रूप से प्रोत्साहित करेगा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत@2047 के विज़न के अनुरूप, 'वोकल फॉर लोकल' पहल के माध्यम से राज्य की समृद्ध विरासत से जुड़े उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य गुजरात के विभिन्न GI टैग प्राप्त उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करते हुए यह सम्मेलन पारंपरिक कारीगरों और उद्यमियों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधे जोड़ने का प्रयास करेगा।

इसी क्रम में मध्य गुजरात की प्रसिद्ध पिथोरा चित्रकला को भी वीजीआरसी के साथ आयोजित होने वाली वाइब्रेंट गुजरात प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। यह प्रदर्शनी 29 जून से 3 जुलाई 2026 तक उसी परिसर में आयोजित होगी।

जीआई टैग किसी उत्पाद की प्रामाणिकता का महत्वपूर्ण प्रमाण होता है, जो उसकी विशिष्ट गुणवत्ता और प्रतिष्ठा को उसके मूल भौगोलिक क्षेत्र से जोड़ता है।

प्राचीन गुफा चित्रों से शुरू हुई यह कला आज आदिवासी घरों की पवित्र मिट्टी की दीवारों से निकलकर कैनवास, कागज और अन्य आधुनिक माध्यमों तक पहुंच चुकी है। छोटाउदेपुर, वडोदरा और पंचमहल जिलों में राठवा, भील और भीलाला समुदायों द्वारा धार्मिक अनुष्ठान के रूप में की जाने वाली यह परंपरा आज पारंपरिक सीमाओं को तोड़ते हुए आर्थिक सशक्तिकरण का नया अध्याय लिख रही है।

कैनवास जैसे पोर्टेबल माध्यमों पर इस कला के विस्तार ने इसे अधिक समावेशी बनाया है और नई पीढ़ी के स्वतंत्र कलाकारों के लिए नए अवसर खोले हैं।

पारंपरिक दीवार चित्रण की मर्यादा को बनाए रखते हुए समकालीन कलाकारों ने इसकी जटिल प्रतीकात्मक शैली को कागज और कैनवास पर सफलतापूर्वक उतारा है। इससे यह धार्मिक परंपरा आज एक व्यवहारिक और सम्मानजनक आजीविका का माध्यम बन गई है, जिसे वैश्विक स्तर पर कलात्मक पहचान मिल रही है।

पारंपरिक मिट्टी के घरों की जगह पक्के मकानों के बढ़ते चलन के बीच इस विरासत को संरक्षित रखने के लिए गुजरात राज्य हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (GSHHDC) अपनी प्रसिद्ध 'गरवी गुर्जरी' ब्रांड के माध्यम से क्लस्टर विकास, प्रत्यक्ष कलाकृतियों की खरीद तथा अन्य संस्थागत सहयोग प्रदान कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में निगम ने पिथोरा कलाकारों से लगभग 6.2 लाख रुपये मूल्य की कलाकृतियां सीधे खरीदी हैं, जिससे उनकी आय में 15 से 30 प्रतिशत तक की स्थायी वृद्धि दर्ज की गई है। वर्तमान में निगम पांच प्रमुख मास्टर कलाकारों के साथ सीधे कार्य कर रहा है तथा अप्रत्यक्ष रूप से हजारों ग्रामीण परिवारों को सहयोग प्रदान कर रहा है। इन पहलों के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए छोटाउदेपुर के कलाकार नारण राठवा ने कहा, "गरवी गुर्जरी द्वारा आयोजित कार्यशालाएं, लाइव डेमोंस्ट्रेशन और मेले हमारे लिए बहुत लाभदायक रहे हैं। पहले हमारी आजीविका केवल गांव में मिलने वाले काम पर निर्भर थी, लेकिन गरवी गुर्जरी के माध्यम से मिले अवसरों के कारण हमारी आय बढ़ी है और आजीविका के नए स्रोत भी विकसित हुए हैं।"

गरवी गुर्जरी कलाकारों को परिवहन एवं स्टॉल सब्सिडी उपलब्ध कराने के साथ-साथ लाइव क्राफ्टिंग प्रदर्शन आयोजित कर उन्हें सीधे ग्राहकों से जोड़ती है। इसके अतिरिक्त नियमित डिजाइन विकास कार्यशालाओं के माध्यम से कलाकारों को आधुनिक उत्पादन तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे वॉल आर्ट, लैंप और होम डेकोर जैसे व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण कर बेहतर आय अर्जित कर सकें। निगम सोशल मीडिया पर 'मेड इन गुजरात हैंडीक्राफ्ट स्टोरी' जैसे डिजिटल स्टोरीटेलिंग अभियानों के माध्यम से पिथोरा चित्रकला की ऑनलाइन बिक्री को भी प्रोत्साहित कर रहा है।

इन प्रयासों की सराहना करते हुए पद्मश्री सम्मानित एवं पिथोरा कला के वरिष्ठ कलाकार परेश राठवा ने कहा, "गरवी गुर्जरी, जो गुजरात का गौरव है, उसने केवल पिथोरा कला को ही नहीं, बल्कि मुझे और मेरे जैसे अनेक स्थानीय कलाकारों को आत्मनिर्भर बनाया है। इस संस्था ने हमारे आदिवासी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और हमारी मिट्टी की खुशबू को दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का ऐतिहासिक कार्य किया है। हमारी प्राचीन कला को आधुनिक दृष्टिकोण के साथ बाजार से जोड़कर इसने नई पीढ़ी को भी अपनी संस्कृति से जोड़ने में सफलता प्राप्त की है। गरवी गुर्जरी के साथ जुड़कर मुझे विपणन और उपभोक्ताओं की पसंद को समझने की नई दृष्टि मिली है। एक कलाकार के रूप में मुझे अपनी कला का वास्तविक सम्मान और मूल्य इसी मंच के माध्यम से प्राप्त हुआ है।"

उन्होंने 'दीवारों से दुनिया तक' की इस यात्रा पर आगे कहा, "गरवी गुर्जरी ने हमारी पवित्र पिथोरा कला को, जो कभी केवल घरों की दीवारों तक सीमित थी, वैश्विक कैनवास प्रदान किया है। इसने दुनिया के सामने पिथोरा चित्रकला को आदिवासी संस्कृति, प्रकृति और आस्था के सशक्त प्रतीक के रूप में स्थापित किया है। गरवी गुर्जरी के साथ जुड़कर हमारे समुदाय के कलाकारों को न केवल स्थायी आजीविका मिली है, बल्कि अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व और सम्मान भी प्राप्त हुआ है।"

गुजरात की पिथोरा चित्रकला को वर्ष 2021 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। प्रत्येक कलाकार रंगों के संयोजन, बॉर्डर और आधुनिक प्रतीकों में अपनी विशिष्ट शैली जोड़ता है, जिसके कारण कोई भी दो चित्र एक जैसे नहीं होते। चित्रों में कहीं पारंपरिक धनुष-बाण दिखाई देते हैं तो कहीं आधुनिक पुलिस जीप, लेकिन इन सभी के केंद्र में एक ही मूल भावना रहती है, मानव, प्रकृति और ईश्वर के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाली एक पवित्र एवं समृद्ध परंपरा।

जूनागढ़ में विधायक गोपाल इटालिया और राजू बोरखतरिया के नेतृत्व में विधायक चैतर वसावा के समर्थन में पदयात्रा आयोजित हुई

- मोरबी ब्रिज, राजकोट और सूरत अग्निकांड के दोषी आज़ाद, लेकिन जनता के लिए लड़ने वाले चैतर वसावा को सज़ा क्यों? : गोपाल इटालिया
- गुजरात में भूमाफिया और लठ्ठाकांड के आरोपी आज़ाद, आदिवासियों का योद्धा जेल में : गोपाल इटालिया
- नकली कचहरी का भंडाफोड़ करना और जल-जमीन के लिए लड़ना क्या अपराध है? : गोपाल इटालिया
- अधिकारों की लड़ाई को अपराध मानने वाली सरकार को आगामी चुनाव में जनता अपने वोट की ताकत से सबक सिखाएगी : गोपाल इटालिया
- AAP आदिवासी समाज और चैतरभाई वसावा के साथ है, इस तानाशाही के सामने झुकने वाले नहीं हैं : गोपाल इटालिया

अहमदाबाद/जूनागढ़/गुजरातः जूनागढ़ में आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया और प्रदेश संगठन मंत्री राजू बोरखतरिया के नेतृत्व में चैतरभाई वसावा के समर्थन में पदयात्रा आयोजित की गई। इस अवसर पर विसावदर के विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता और गुजरात के आदिवासी समाज के योद्धा चैतरभाई वसावा के खिलाफ भाजपा सरकार ने कानून का दुरुपयोग करके, कानूनी प्रक्रिया के साथ छेड़छाड़ करके और षड्यंत्र रचकर उन्हें राजनीति से दूर करने तथा विधायक पद से हटाने का दुर्भावनापूर्ण कार्यक्रम चलाया है और उन्हें सात साल की जेल की सज़ा दिलवाई है। चैतरभाई वसावा का अपराध क्या है? चैतरभाई का अपराध आदिवासी समाज को जागरूक करना है। आदिवासी समाज के जल, जमीन और जंगल के अधिकारों के लिए लड़ना क्या अपराध है? आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है, उन विस्थापित आदिवासियों के लिए लड़ना अपराध है, आदिवासी क्षेत्रों में नकली कार्यालयों का भंडाफोड़ करना अपराध है, और समाज के लिए, युवाओं के लिए तथा लोगों के लिए लड़ना अपराध है। यही काम करने के कारण उन्हें सात साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। गुजरात में अनेक जमीन माफिया, घोटाले करने वाले माफिया, ठेकेदार माफिया, घटिया गुणवत्ता की दवाइयाँ बेचने वाले और नकली सामान बनाने वाले हजारों अपराध कर रहे हैं।

विधायक गोपाल इटालिया ने आगे कहा कि पूरे गुजरात में ऐसे अपराध करने वाले एक भी व्यक्ति को सात साल की सज़ा नहीं हुई। मोरबी में पुल टूट गया, फिर भी किसी को सात साल की सज़ा नहीं हुई। राजकोट के अग्निकांड में अनेक निर्दोष लोग जलकर मर गए, फिर भी किसी को सात साल की सज़ा नहीं हुई। सूरत अग्निकांड के पीड़ित परिवार आज भी न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उसके आरोपियों को सात साल की सज़ा नहीं हुई। गुजरात के बोटाद में लठ्ठाकांड हुआ, जिसमें पचास से अधिक लोगों की मौत हो गई, फिर भी आरोपियों को सात साल की जेल की सज़ा नहीं हुई। हॉस्टल में घुसकर युवतियों के साथ बलात्कार करने वाले अपराधियों को सात साल की जेल की सज़ा नहीं होती! लेकिन चैतर वसावा ने जनता को जगाने और जनता के अधिकारों के लिए लड़ने का काम किया, तो उन्हें मामूली धाराओं में सात साल की जेल की सज़ा दे दी गई! हम आम आदमी पार्टी के रूप में गुजरात के आदिवासी समाज और चैतरभाई वसावा के साथ खड़े हैं। जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लड़ते रहेंगे और इस तानाशाही के सामने झुकने वाले नहीं हैं। गुजरात की जनता और आदिवासी युवाओं से मेरी एक विनम्र अपील है कि यदि आप मानते हैं कि एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को मामूली धाराओं के तहत सात साल तक जेल में डालने का काम भाजपा ने किया है और यह उचित नहीं है, तो मैं सभी से अपील करता हूँ कि आगामी चुनावों में भाजपा को एक भी वोट नहीं मिलना चाहिए। सभी वोट चैतरभाई वसावा और आम आदमी पार्टी को दीजिए।

शराब और ड्रग्स बेचने वाले बाहर, लेकिन लोगों की आवाज़ उठाने वाले चैतर वसावा जेल में : AAP

- विधायक चैतर वसावा के समर्थन में AAP की राज्यव्यापी "सपोर्ट मार्च"
- अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा सहित सभी जिलों में AAP सड़कों पर उतरी
- चैतर वसावा को विधायक पद से हटाने के लिए रचा गया षड्यंत्र : AAP
- आदिवासी समाज की आवाज़ को दबाने की कोशिश : AAP
- जनता की आवाज़ उठाने वाले को ही भेजा गया जेल : AAP
- भाजपा के सामने नहीं झुके, इसलिए चैतर वसावा को बनाया गया निशाना : AAP

अहमदाबाद/सूरत/वडोदरा/राजकोट/जामनगर/भावनगर/भरूच/नर्मदा/छोटाउदेपुर/वलसाड/डीसा/गिर सोमनाथ/देवभूमि द्वारका/सुरेंद्रनगर/जूनागढ़/कच्छ/गांधीनगर/गुजरातः आम आदमी पार्टी के डेडियापाड़ा से विधायक और आदिवासी समाज के लोकप्रिय नेता चैतर वसावा के खिलाफ षड्यंत्र के तहत एक मामला दर्ज किया गया, जिसमें विधायक चैतर वसावा सहित कुल नौ लोगों को सात वर्ष की सज़ा सुनाई गई। इसके विरोध में तथा विधायक चैतर वसावा के समर्थन में आम आदमी पार्टी ने आज अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट, जामनगर, भावनगर, अमरेली सहित पूरे गुजरात में "सपोर्ट मार्च" का आयोजन किया। अहमदाबाद में प्रदेश कार्यालय से इनकम टैक्स सर्कल तक आम आदमी पार्टी द्वारा इस सपोर्ट मार्च का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष गौरी देसाई, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं प्रदेश संगठन मंत्री डॉ. करन बारोट, आम आदमी पार्टी की छात्र इकाई ASAP के प्रदेश अध्यक्ष धार्मिक माथुकिया, ASAP के अहमदाबाद शहर अध्यक्ष यात्रिक पटेल, मालधारी सेल के प्रदेश अध्यक्ष किरण देसाई, महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नेहा केवलरामाणी, महिला मोर्चा की प्रदेश संगठन मंत्री कश्मीरा मेहता, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष हार्दिक खोखर, युवा मोर्चा के प्रदेश संगठन मंत्री जुबेर शेख, अहमदाबाद पश्चिम लोकसभा प्रभारी विपुल पटेल, आम आदमी पार्टी के नेता राजेश दीक्षित, मुकेश चौहान, दीपक देसाई सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे और विधायक चैतर वसावा के समर्थन में नारे लगाए।

आदिवासी समाज के लिए संघर्ष करने वाले, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए लड़ने वाले तथा गुजरात के युवाओं की आवाज़ उठाने वाले आदिवासी समाज के लोकप्रिय विधायक चैतर वसावा को षड्यंत्र के तहत कानून का दुरुपयोग करके जेल भेजा गया है। जब से विधायक चैतर वसावा डेडियापाड़ा से चुनाव जीते हैं, तभी से भाजपा ने उन्हें डराने-धमकाने और लालच देने की अनेक कोशिशें कीं, लेकिन विधायक चैतर वसावा भाजपा के सामने नहीं झुके। इसी कारण भाजपा सरकार ने तंत्र का दुरुपयोग करते हुए बार-बार चैतर वसावा के खिलाफ मामले दर्ज किए और उन्हें कई बार जेल भेजा। यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि भाजपा सरकार षड्यंत्र रचकर चैतर वसावा को विधायक पद से हटाना चाहती है। क्योंकि चैतर वसावा सड़क से लेकर विधानसभा तक आदिवासी समाज सहित पूरे गुजरात के लोगों की आवाज़ उठाते हैं और भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने लाते हैं, इसलिए विधायक चैतर वसावा भाजपा की आँखों में खटकते थे। गुजरात में भाजपा के अनेक नेताओं के खिलाफ वर्षों से मामले चल रहे हैं, लेकिन उन्हें सज़ा नहीं होती। भूमाफिया, भ्रष्टाचारी, खराब सड़क और पुल बनाने वाले ठेकेदार, शराब और ड्रग्स बेचने वाले माफिया सहित अनेक लोग गलत काम करने के बावजूद खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि जनता की आवाज़ उठाने वाले चैतर वसावा को जेल भेज दिया गया है। विधायक चैतर वसावा को न्याय मिलने तक आम आदमी पार्टी अपनी लड़ाई जारी रखेगी।

पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है: केंद्र के बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर सवाल तेज कर दिए हैं

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत।

देश में हर सुबह तनाव बढ़ता जा रहा है क्योंकि भाजपा सरकार के शासन में हर दिन नए घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और देश के नागरिक अब एक अंतर्निहित भय से ग्रस्त हैं। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को पीटीआई को बताया कि पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात दोहराई।

पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अनुसार, गैर-नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि कल यह निर्णय नहीं लिया गया कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पिछले बारह वर्षों में भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है।

जबकि पहले के उच्च न्यायालय के फैसलों में यह कहा गया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या यहां तक कि मतदाता पहचान पत्र भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। 2019 में, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर प्रश्नोत्तर सत्र में, प्रेस सूचना ब्यूरो ने लिखा था कि किसी भी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण नागरिकता नियम,

2009 के आधार पर किया जाता है। ये नियम नागरिकता अधिनियम, 1955 पर आधारित हैं। यह नियम सार्वजनिक रूप से मान्य है। भारत का नागरिक बनने के पांच तरीके हैं: (1) जन्म से नागरिकता (2) वंश से नागरिकता (3) पंजीकरण द्वारा नागरिकता (4) प्राकृतिककरण द्वारा नागरिकता (5) निगमन द्वारा नागरिकता। इस प्रकार, यदि आपके पास भारतीय नागरिक होने के उपरोक्त आधिकारिक प्रमाण हैं, तो आप भारतीय नागरिक कहलाते हैं।

इस संबंध में, राज्यसभा सांसद कपिल सिबल ने भी सरकार पर हमला करते हुए कहा, फिर नागरिकता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज है?

अंत में, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि ऐसा लगता है कि आज भारतीय नागरिकता का एकमात्र प्रमाण हिंदू होना और भाजपा मतदाता होना ही आवश्यक है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं चलेगा।

नासिरनगर विध्वंस मामले में उच्च न्यायालय के कड़े सवाल, एसएमसी, पुलिस और टोरेंट पावर से जवाब मांगे

(छगनलाल मेवाड़ा द्वारा) सूरत

सूरत के नासिर नगर विध्वंस मामले में, जो राज्य और देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, अधिकारियों ने मनमाने ढंग से गरीबों को बेघर कर दिया है। अब, उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस विभाग और एसएमसी में हलचल मचा दी है।

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक तीखा सवाल पूछा, "सूरत पुलिस आयुक्त ने विध्वंस के संबंध में शिकायत क्यों नहीं दर्ज की?" इस गंभीर मामले के लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है। टॉरेंट पावर और डीसीपी नाकुम भी समान रूप से जिम्मेदार हैं।

नासिर नगर विध्वंस मामले में 26 याचिकाकर्ताओं ने गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें राज्य सरकार, एसएमसी, सूरत पुलिस आयुक्त, एसओजी डीसीपी राजदीपसिंह नाकुम, पुलिस एवं एसएमसी कर्मचारी और टॉरेंट पावर को पक्षकार बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि एसओजी डीसीपी (राजदीपसिंह नाकुम) वहां अवैध रूप से उपस्थित थे, तो उन्हें अगली सुनवाई में अदालत के समक्ष पेश

होना होगा। क्योंकि यह विध्वंस बिना किसी सूचना, निवेदन का अवसर या पंचनामा के किया गया था। 30 मई को सूरत के नासिर नगर में एसएमसी द्वारा 150 से अधिक मकान ध्वस्त कर दिए गए थे। उच्च न्यायालय ने पूछा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह तोड़फोड़ एसएमसी द्वारा की गई थी? याचिकाकर्ताओं की ओर से दिया गया उत्तर यह था कि तोड़फोड़ स्थल पर एसएमसी के अधिकारी और 20 से 25 पुलिसकर्मी एवं अन्य कर्मचारी मौजूद थे। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि सूरत नगर पुलिस आयुक्त को यह उत्तर देना चाहिए कि तोड़फोड़ एसएमसी द्वारा की गई थी या किसी और द्वारा? यदि एसओजी के डीसीपी कानूनी रूप से उपस्थित थे, तो उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, टॉरेंट पावर को यह भी बताना चाहिए कि उन्होंने नासिर नगर का बिजली कनेक्शन किसके आदेश पर काटा? इस संवेदनशील मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उनके पास अधिकार है। न्यायालय को संबंधित अधिकारियों से स्पष्ट उत्तर प्राप्त करना चाहिए। इस याचिका की पहली सुनवाई सोमवार, 29 जून की सुबह होगी, जिसमें टॉरेंट पावर के वकील भी उपस्थित रहेंगे। इस प्रकार, अंततः न्यायालय ने गरीबों की बात सुन ली है।

राजकोट में अतिक्रमण हटाने से ज्यादा चर्चा खाने के बिल की, तीन दिन में चाय-नाश्ते पर 27 लाख रुपये खर्च का दावा, सियासत गरमाई

राजकोट। गुजरात के राजकोट शहर के जंगलेश्वर क्षेत्र में हाल ही में चलाए गए मेगा अतिक्रमण हटाओ अभियान का मामला अब एक नए विवाद में घिर गया है। अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई पहले ही राजनीतिक बहस का विषय बनी हुई थी, लेकिन अब इस अभियान के दौरान कर्मचारियों और पुलिस बल के खान-पान पर हुए लाखों रुपये के खर्च ने नगर निगम को विपक्ष के निशाने पर ला दिया है। सामने आए दस्तावेजों के अनुसार केवल तीन दिनों के अभियान में चाय, नाश्ता, मिनरल वाटर और अन्य व्यवस्थाओं पर लगभग 27.20 लाख रुपये खर्च किए गए। खर्च का ब्योरा सार्वजनिक होने के बाद इसे लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

जानकारी के अनुसार जंगलेश्वर इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम, पुलिस, बिजली विभाग, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के संयुक्त अभियान में हजारों कर्मचारियों की तैनाती की गई थी। इसी दौरान खान-पान और अन्य व्यवस्थाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों को ठेके दिए गए। अब इन व्यवस्थाओं से जुड़े बिल सामने आने के बाद पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है।

सामने आए खर्च के विवरण के मुताबिक अभियान के दौरान कर्मचारियों के लिए करीब 21 हजार कप चाय और लगभग चार हजार बोतल नींबू पानी की व्यवस्था की गई। इसके अलावा बड़ी मात्रा में कॉफी, बिस्कुट और अन्य खाद्य सामग्री भी वितरित की गई। इन मदों का बिल लगभग 6.30 लाख रुपये बताया गया है, जो आराधना टी स्टॉल के नाम पर तैयार किया गया है। वहीं नाश्ते के लिए प्रेमवती रेस्टोरेंट का बिल करीब 20 लाख रुपये का बताया गया है। इस बिल में काजू, खजूर रोल, वेफर, समोसे तथा अन्य खाद्य सामग्री शामिल है। उपलब्ध विवरण के अनुसार नाश्ते की एक प्लेट की कीमत लगभग 231 रुपये दर्ज की गई है, जिसने पूरे मामले को और अधिक विवादास्पद बना दिया है।

इतना ही नहीं, अभियान के दौरान पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं पर भी भारी खर्च का दावा किया गया है। दस्तावेजों के अनुसार मिनरल वाटर की आपूर्ति पर लगभग 12.40 लाख रुपये खर्च किए गए, जबकि मंडप और अन्य अस्थायी सुविधाओं की व्यवस्था पर करीब 6.70 लाख रुपये का बिल तैयार किया गया। इन दोनों सेवाओं का ठेका उमिया मंडप सर्विस को दिया गया था। हालांकि नगर निगम के सूत्रों का कहना है कि यह पूरा खर्च अभी तक स्थायी समिति की अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मामले के तूल पकड़ने के बाद राजकोट नगर निगम ने अपनी ओर से सफाई भी दी है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जयेश वंकानी ने कहा कि जंगलेश्वर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान अत्यंत व्यापक स्तर पर चलाया गया था। उन्होंने बताया कि कार्रवाई आठ अलग-अलग क्षेत्रों में एक साथ संचालित की गई थी और इसमें नगर निगम के अलावा पुलिस, पीजीवीसीएल, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा बड़ी संख्या में श्रमिकों सहित करीब 4,800 कर्मचारी तैनात किए गए थे। इतनी बड़ी संख्या में मौजूद कर्मचारियों के लिए भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना प्रशासन की जिम्मेदारी थी।

डॉ. वंकानी ने यह भी कहा कि सभी ठेके निर्धारित प्रक्रिया के तहत स्वीकृत एजेंसियों को दिए गए थे और खर्च नियमों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने दावा किया कि नाश्ते में वितरित काजू, खजूर रोल, वेफर और समोसे सहित सभी खाद्य सामग्री के बिल उपलब्ध हैं तथा भुगतान पूरी तरह दस्तावेजों के आधार पर किया गया है। उनके अनुसार खर्च में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई है और आवश्यकता पड़ने पर सभी रिकॉर्ड सार्वजनिक किए जा सकते हैं। नगर निगम की सफाई के बावजूद विपक्ष इस मामले को लेकर हमलावर बना हुआ है। कांग्रेस ने खर्च को अत्यधिक बताते हुए इसकी स्वतंत्र जांच की मांग की है।

दादा की उंगली पकड़कर जा रहा था मासूम, शेरनी ने झपट्टा मारकर उठा ले गई; एक किलोमीटर दूर मिला शव, अमरेली में दहशत

अमरेली। गुजरात के अमरेली जिले में इंसानों और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष ने एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना को जन्म दिया। गिर वन क्षेत्र से सटे खांभा तालुका के चतुरी गांव में एक शेरनी ने पांच वर्षीय मासूम बच्चे पर उस समय हमला कर दिया, जब वह रात में अपने दादा के साथ दूध लेने जा रहा था। दादा की आंखों के सामने शेरनी बच्चे को मुंह में दबाकर जंगल की ओर भाग गई। ग्रामीणों ने काफी देर तक उसकी तलाश की, लेकिन करीब एक किलोमीटर दूर बच्चे का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है, जबकि ग्रामीणों में वन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर गहरा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है।

मृतक की पहचान पांच वर्षीय जियान देवकुंभाई सीधा के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार घटना रात के समय हुई, जब जियान अपने दादा की उंगली पकड़कर गांव में दूध लेने जा रहा था। रास्ते में अंधेरे का फायदा उठाकर घात लगाए बैठी एक शेरनी ने अचानक हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि दादा बच्चे को बचाने का कोई मौका ही नहीं पा सके। शेरनी मासूम को अपने जबड़ों में दबाकर तेजी से जंगल की ओर भाग निकली।

घटना के बाद दादा के शोर मचाने पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे। लोगों ने लाठियां और टॉर्च लेकर जंगल की ओर बच्चे की तलाश शुरू कर दी। परिजनों का कहना है कि कुछ युवकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर शेरनी का पीछा भी किया और बच्चे को छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। काफी देर तक चले खोज अभियान के बाद गांव से लगभग एक किलोमीटर दूर बच्चे का शव बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर परिजन और ग्रामीण स्तब्ध रह गए।

घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अधिकारियों के अनुसार करीब नौ घंटे तक चले अभियान में एक शेरनी को बेहोश कर पकड़ लिया गया, जबकि कुल पांच शेरों को रेस्क्यू कर पिंजरों में सुरक्षित रखा गया। वन विभाग ने बताया कि सभी पकड़े गए शेरों की चिकित्सकीय जांच कराई गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि हमले में कौन-सा शेर शामिल था।

प्रारंभिक जांच के दौरान पकड़े गए शेरों में से एक की उल्टी में बच्चे के अवशेष मिलने की पुष्टि हुई है। अधिकारियों ने बताया कि इन अवशेषों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, जिससे घटना से संबंधित वैज्ञानिक प्रमाण जुटाए जा सकें। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इस घटना ने एक बार फिर गिर क्षेत्र से सटे गांवों में वन्यजीवों की बढ़ती आवाजाही और मानव सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ समय से शेर लगातार आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। उनका आरोप है कि वन विभाग को पहले से शेरों की गतिविधियों की जानकारी होने के बावजूद पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए।

स्थानीय लोगों के अनुसार यह अमरेली जिले में पिछले एक महीने के भीतर शेर के हमले की तीसरी घटना है। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने ग्रामीणों की चिंता और बढ़ा दी है। लोगों का कहना है कि बच्चों और बुजुर्गों का शाम ढलने के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई गांवों में लोग अब समूह बनाकर ही खेतों और अन्य कार्यों के लिए बाहर जा रहे हैं।

घटना के बाद ग्रामीणों ने प्रभावित क्षेत्रों में वन विभाग की गश्त बढ़ाने, आबादी के आसपास सक्रिय शेरों की नियमित निगरानी करने और संभावित खतरे वाले इलाकों में तत्काल सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन गांवों में शेरों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है, वहां लोगों को समय रहते सतर्क करने के लिए प्रभावी चेतावनी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और क्षेत्र में शेरों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही ग्रामीणों से अपील की गई है कि रात के समय अकेले बाहर न निकलें और किसी भी वन्यजीव की गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल विभाग को सूचना दें।

यह दर्दनाक घटना एक बार फिर इस चुनौती को सामने लेकर आई है कि गिर क्षेत्र में बढ़ती शेरों की संख्या और उनके प्राकृतिक आवास के आसपास फैलती मानव बस्तियों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा, दोनों को साथ लेकर चलना अब प्रशासन और वन विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन गया है।